

1046

[2023] 6 एस. सी. आर. 1046

/

[2023] 6 एस सी आर।

/

एल. आर. एस. के माध्यम से गुरजित सिंह (डी)

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 4826-4828)

/

मार्च 03,2023

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना।]

लाइसेंस-एक लाइसेंस धारक, यदि अधिकार के रूप में अपनी दुकान के बगल में और/या उसके सामने नीलामी मंच के आवंटन का हकदार है-आयोजित:दुकान में व्यापार करना और नीलामी मंच पर व्यवसाय करना दोनों अलग-अलग और विशिष्ट हैं-केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है और वह किसी विशेष दुकान में व्यवसाय कर रहा है, वह अधिकार के रूप में नीलामी मंच का हकदार नहीं है और वह भी अपनी दुकान के सामने और/या उससे सटे-ऐसे दावे का समर्थन करने वाला कोई नियम और/या विनियमन और/या दिशानिर्देश अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था-अपीलार्थी के पक्ष में किसी विशिष्ट नियम के अभाव में, उसकी दुकान के ठीक सामने और/या उससे सटे आवंटन का दावा करने का अधिकार जब प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में आवंटन नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था, उच्च न्यायालय

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 4826-4828।

/

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2011 के एल. पी. ए. संख्या 2130 में एल. पी. ए. Nos.2130,2011 के 2131 में दिनांकित <आई. डी. 3 और 2013 के सी.

एम. No.5249 में दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, नरेश बख्शी, सुश्री हर्षिका वर्मा, तुषार बख्शी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

वत्सल जोशी, शरद कुमार सिंघानिया, भुवन कपूर, वरुण चुघ, जी. एस. मक्कर, चंद्र प्रकाश, सुश्री दिलमरिग नयानी, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, तुषार बाथीजा, श्री पाल सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

1046 ए.

1047

गुरुजीत सिंह (डी) थ्रू एल. आर. एस. बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ और ओ. आर. एस.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में लेटर पेटेंट अपील संख्या 2130/2011 और 2131/2011 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और दिनांक 23.10.2013 के आदेश और एल. पी. ए. संख्या 2130/2011 में सीएम संख्या 5249/2013 में पारित किए गए बाद के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त लेटर पेटेंट अपीलों को खारिज कर दिया है, जिससे रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि होती है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2.वर्तमान अपीलों के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

2.1 कि अपीलार्थी कृषि उपज बाजार, चंडीगढ़ में स्थित दुकान संख्या 27 का मालिक बन गया।इसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 उक्त दुकान का किरायेदार था।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 दोनों के पास बाजार क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आवश्यक लाइसेंस थे।प्रत्यर्थी सं. 5 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा निष्कासन कार्यवाही शुरू की गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन के आदेश की पुष्टि की गई।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 5 वर्ष 2007 में दुकान संख्या 12 में किरायेदार के रूप में स्थानांतरित हो गया और नई दुकान में पता बदलने के लिए आवेदन किया, हालांकि, उसे अस्वीकार कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपना लाइसेंस सौंपने और

नए के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया।अपीलार्थी ने फल/सब्जियाँ बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया और राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इसे जारी किया।तब से, अपीलार्थी अपने स्वामित्व वाली दुकान संख्या 27 से व्यवसाय चला रहा है।प्रत्यर्थी संख्या 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांकित 05.07.2007 आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा नई दुकान संख्या 12 में पता बदलने के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।05.07.2007 दिनांकित आदेश पर रोक लगा दी गई थी।यह रोक 31.03.2009 यानी प्रतिवादी संख्या 5 के लाइसेंस की वैधता तक जारी रही।इसके बाद, बाजार समिति, चंडीगढ़ ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के आवेदन को खारिज कर दिया।यही उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका का विषय था जो रिट याचिका संख्या 5886/2009 थी।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 ने पुराने लाइसेंस के अनुसार कार्य करना जारी रखा।कि अनुज्ञप्ति समिति अनुज्ञप्ति के अंतर्गत गठित की गई थी

/

/

/

/

/

1048

/

[2023] 6 एस सी आर।

/

नीलामी प्लेटफॉर्म नियम, 1981 ने निर्णय लिया कि प्लेटफॉर्म में साइट "एक साइट एक दुकान" के आधार पर आवंटित की जाएगी और प्रतिवादी संख्या 5 का नाम अपीलार्थी के साथ सह-आवंटनकर्ता के रूप में दिखाया गया था।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जो रिट याचिका संख्या 12684/2009 थी।उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय और दिनांक 26.09.2011 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 5886/2009 की अनुज्ञात और निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाए।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 दुकान संख्या 27 के सामने मंच का उपयोग करने का हकदार है जब तक कि मंच का उपयोग करने के अधिकारों के मुद्दे से संबंधित अधिनियम या नियमों में संशोधन के माध्यम से कोई वैकल्पिक नीति नहीं आती है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि

मंच का उपयोग करने और बाजार क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार दोनों अलग-अलग हैं और दोनों अधिकार सीधे जुड़े नहीं थे।

/

/

2.2 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त पत्रों की पेटेंट अपीलों को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि दुकान का उपयोग करने का अधिकार और/या लाइसेंस होने और मंच का उपयोग करने का अधिकार सीधे संबंधित नहीं हैं। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 1970 से प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, यानी अपीलकर्ता के लाइसेंस प्राप्त करने से बहुत पहले और इसलिए, एक वरिष्ठ लाइसेंसधारी होने के नाते, उसे आवंटित प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यानी दुकान संख्या 27 के सामने। 2.3 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट मूल रिट याचिकाकर्ता-लाइसेंस धारक और दुकान संख्या 27 के मालिक, जो दुकान संख्या 27 के सामने मंच का उपयोग करने के अधिकार का भी दावा कर रहे हैं, ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

/

3. प्रश्नार्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मूल प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में नीलामी मंच के आवंटन की पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है।

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ अपीलार्थी को वर्ष 2007 में लाइसेंस दिया गया था, हालाँकि, जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 5 ए है

/

1049

गुरुजीत सिंह (डी) थ्रू एल. आर. एस. बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

संबंधित रूप से, उन्होंने वर्ष 2009 में एक नए लाइसेंस/नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और उन्हें वर्ष 2010 में एक नया लाइसेंस जारी किया गया और इसलिए, वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थी प्राथमिकता का हकदार था।

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2009 में नए लाइसेंस/नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय भी, प्रतिवादी संख्या 5 ने 20.08.2009 दिनांकित एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि वह नीलामी मंच पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेगा। कि वास्तव में लाइसेंस उक्त शपथपत्र के बाद ही जारी किया गया था।

/

3.3 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि दुकान और नीलामी मंच पर व्यवसाय करना दोनों अलग और अलग हैं। प्लेटफॉर्म में किसी विशेष साइट का उपयोग करने का अधिकार बोर्ड की स्पष्ट नीति यानी "एक साइट एक दुकान" को देखते हुए विशेष संबंधित दुकान का उपयोग करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

/

3.4 यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ अपीलार्थी व्यवसाय कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है और उसे दुकान संख्या आवंटित की गई है। 27 और इसलिए, वह दुकान संख्या 27 से सटे और/या उसके सामने नीलामी मंच के आवंटन का हकदार है।

/

3.5 यह आगे तर्क दिया जाता है कि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 5 का संबंध है, वह दुकान संख्या 12 में व्यवसाय कर रहा है, इसलिए अपीलार्थी को नीलामी मंच पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देना जो दुकान संख्या 27 से सटा हुआ है और प्रत्यर्थी संख्या 5 को नीलामी मंच आवंटित करना जो दुकान संख्या 5 में व्यवसाय कर रहा है। 12, दुकान संख्या 27 के ठीक बगल में अनुचित और मनमाना है।

/

3.6 इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी (ओं) ने प्रतिवादी संख्या 5 को स्थल के सह-आवंटन को चुनौती देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश से संपर्क किया। कि किसी भी मामले में अपीलार्थी इस तरह की चुनौती में सफल नहीं होते हैं, वे उस स्थिति की तुलना में बदतर नहीं हो सकते हैं जिसमें वे रिट याचिका दायर करने से पहले थे।

/

4. चंडीगढ़ बाजार समिति की ओर से पेश विद्वान वकील श्री वत्सल जोशी ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद, अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर बाजार समिति द्वारा विचार और विचार किया गया है और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए बाजार समिति द्वारा एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

/

/

1050

/

[2023] 6 एस सी आर।

4.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नीलामी मंच का आवंटन नीति के अनुसार किया जाना है। यह कि उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि दुकान में और नीलामी मंच पर व्यवसाय करना अलग और विशिष्ट है। कि इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से कोई नीति और/या नियम नहीं बताया गया है कि एक लाइसेंस धारक नीलामी मंच के व्यवसाय और/या आवंटन को उसके द्वारा कब्जा की गई दुकान के ठीक बगल में और/या उसके सामने करने का हकदार है। 4.2 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को 1970 से व्यवसाय करते हुए पाया गया था और उसके बाद, उसने वर्ष 2009 में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया; उन्हें दुकान संख्या 27 के सामने मंच आवंटित किया गया है।

/

/

4.3 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता और/या संबंधित दुकान में व्यवसाय करने वाला कोई अन्य लाइसेंस धारक किसी विशेष स्थान पर नीलामी मंच के अधिकार दावा आवंटन के मामले के रूप में नहीं कर सकता है।

4.4 यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार, बाजार समिति में मौजूदा शेड 10.06.2007 पर ढह गए और उसके बाद, वर्ष 2009 में शेड का पुनर्निर्माण किया गया। इसके बाद, सचिव कृषि, यू. टी. चंडीगढ़ ने पहली बार में सिद्धांत और दिशा-निर्देश निर्धारित किए, वे सभी आवंटी, जिन्हें <आई. डी. 1 पर शेड गिरने से पहले काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, वे शेड/स्थान आवंटित करने के हकदार थे क्योंकि वे उस तारीख को मौजूद थे जब शेड ढह गया था। कि अपीलार्थी को लाइसेंस 16.07.2007 पर जारी किया गया था, जबकि शेड 10.06.2007 पर ढह गए थे, इसलिए, अपीलार्थी के पास 10.06.2007 पर ढहने से पहले

शेड का कब्जा नहीं था और इसलिए, उसका मामला उपरोक्त नीति के अंतर्गत नहीं आता है।
4.5 यह भी तर्क दिया जाता है कि शेड आवंटित करने में बाजार समिति की कार्रवाई कृषि विभाग, चंडीगढ़ के सचिव द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/नीति के अनुरूप है।

/

/

/

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस तरह के प्रतिवादी संख्या 5 10.06.2007 पर शेड के ढहने के समय भी मंच पर व्यवसाय कर रहा था और उसके पास 1970 से वैध लाइसेंस था। हालांकि, नवनिर्मित शेड के आवंटन के समय, फर्म का लाइसेंस नवीनीकरण न होने के कारण मान्य नहीं था और लाइसेंस देने का मामला ए में विचार के लिए लंबित था।

/

/

1051

गुरजित सिंह (डी) थ्रू एल. आर. एस. बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

समिति का कार्यालय, और उसे अंततः फरवरी, 2010 के महीने में प्रदान किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद समिति के गठन पर शेड का आवंटन प्रतिवादी संख्या 5 को किया गया था, जो समिति का लाइसेंसधारी और शेड का कब्जा धारक था। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए। 6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को देख चुके हैं।

/

6.1 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलकर्ता शेड/नीलामी मंच का दावा कर रहा है जो दुकान संख्या 27 और/या किसी अन्य स्थान के ठीक बगल में और/या उसके सामने है। हालांकि, अपीलकर्ता शेड/नीलामी मंच के आवंटन के संबंध में कोई विशिष्ट नियम और/या विनियम स्थापित करने और/या दिखाने में असमर्थ है और वह भी दुकान के ठीक बगल में और/या दुकान के सामने जिसमें कोई विशेष व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है। इसलिए, अपने पक्ष में

किसी विशिष्ट अधिकार के अभाव में, अपीलार्थी अपनी दुकान संख्या 27 के ठीक बगल में और/या उसके सामने शेड/नीलामी मंच के आवंटन के लिए अनुरोध नहीं कर सकता था।

/

/

6.2 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अन्य व्यक्तियों को भी विभिन्न स्थानों पर दुकानें/नीलामी मंच आवंटित किए जाते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि नीलामी मंचों की उपलब्धता की तुलना में व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है।

/

6.3 इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा 06.05.2016 और 05.08.2016 पर पारित आदेशों के अनुसार, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी ने अभ्यावेदन किया। आदेश इस प्रकार हैं:-

/

“विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया का कहना है कि कुछ अन्य मंच भी उपलब्ध हैं। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 इस बात पर विचार कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता को ऐसा एक मंच आवंटित किया जा सकता है या नहीं।

/

याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में अभ्यावेदन देने का अधिकार है।

अगस्त, 2016 के महीने में मामले को सूचीबद्ध करें।” XXX

/

1052

/

[2023] 6 एस सी आर।

“याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि मंच संख्या 13 उपलब्ध है। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मामला विचाराधीन है और चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

/

हम आशा करते हैं कि उत्तरदाता इसे अनुकूल रूप से विचार करेंगे। चार सप्ताह के बाद याचिकाओं को सूचीबद्ध करें। ”

यहां तक कि अभ्यावेदन को भी अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने की अनुमति दी गई थी कि कुछ अन्य मंच उपलब्ध हैं और इसके लिए, इस न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा एक मंच अपीलार्थी को आवंटित किया जा सकता है या नहीं। कि इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन किया गया था जिसे समिति द्वारा एक विस्तृत आदेश द्वारा निपटाया और अस्वीकार कर दिया गया है जो स्वयं व्याख्यात्मक है।

/

/

6.4 अभ्यावेदन/आदेश में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पहले शेड 10.06.2007 पर ढह गया था और उसके बाद, वर्ष 2009 में शेड का पुनर्निर्माण किया गया था और कृषि सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक नीतिगत निर्णय लिया गया था, कि पहली बार में, वे सभी आवंटी, जिन्हें 10.06.2007 पर शेड गिरने से पहले काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, वे शेड/स्थान आवंटित करने के हकदार थे क्योंकि वे उस तारीख को मौजूद थे जब शेड ढह गया था। इसके बाद, सचिव द्वारा निर्देशित नीलामी मंचों के आवंटन से संबंधित सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटन किया गया है। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

/

/

“1. सबसे पहले, उन सभी आवंटियों को, जिन्हें 10.06.2007 पर शेड के ढहने से पहले काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, शेड/स्थान आवंटित किए जाएंगे क्योंकि वे उस तारीख को बाहर निकले थे जब शेड ढह गया था।

2. यदि उसके बाद, अधिक स्थान उपलब्ध हैं, तो उन स्थानों का विज्ञापन किया जाएगा और आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को वास्तविक लाइसेंस धारकों या उन लाइसेंसधारियों से नए आवेदन किए जाएंगे जिनके लाइसेंस नवीनीकरण के लिए देय हैं और आवेदन बुलाने की तारीख को सक्षम प्राधिकारी के साथ नवीनीकरण के लिए लंबित हैं, कम से कम 20 दिनों की उचित सूचना देने के बाद बुलाए जाएंगे।

/

/

1053

गुरुजीत सिंह (डी) श्रू एल. आर. एस. बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध स्थान की संख्या से अधिक है, तो अध्यक्ष, बाजार समिति, कृषि सचिव, कृषि विपणन बोर्ड और उपस्थित होने की इच्छा रखने वाले आवेदकों की उपस्थिति में ड्रा का आयोजन किया जाएगा। ड्रा के आधार पर साइटों/कार्यस्थलों का और आवंटन किया जाएगा।

/

3. इन निर्देशों का पालन तब तक किया जाएगा जब तक सरकार अधिनियम के अंतर्गत एक नया नियम नहीं बनाती और नए दिशानिर्देश नहीं देती।

इस मामले में मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि कोई भी आवंटन जो पूर्ववर्ती आबंटियों के अलावा अन्य लोगों को किया गया है, जो 10.06.2007 पर बैठे थे और अपना व्यवसाय कर रहे थे, न्यायसंगत और वैध नहीं है और इसे अलग करने की आवश्यकता है।

/

मैं बाजार समिति को निर्देश देता हूँ कि वे उन अलाटियों को आवंटित स्थल/शेड को रद्द करने के लिए नोटिस जारी करें जो 10.06.2007 पर आवंटित नहीं थे और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित कर सकते हैं जो मैंने इस आदेश में निर्धारित किया है। "

/

/

6.5 इसके बाद, कृषि सचिव द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/सिद्धांतों के अनुसार आवंटन किया गया है। इन परिस्थितियों अंतर्गत, अपीलकर्ता नीलामी मंचों के आवंटन के संबंध अंतर्गत सचिव द्वारा जारी सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के पालन के लिए किसी भी तरजीही व्यवहार और/या आवंटन का हकदार नहीं है। अपीलार्थी के साथ बाजार और नीलामी मंच पर व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों के बराबर और समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

/

6.6 जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, दुकान में व्यापार करना और नीलामी मंच पर व्यवसाय करना, दोनों अलग-अलग और विशिष्ट हैं। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है और वह किसी विशेष दुकान में व्यवसाय कर रहा है, वह अधिकार के रूप में नीलामी मंच का हकदार नहीं है और वह भी अपनी दुकान के सामने और/या उसके बगल में। इस तरह के दावे का समर्थन करने वाला कोई नियम और/या विनियमन और/या दिशानिर्देश उच्च न्यायालय या यहां तक कि इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

/

/

1054

/

[2023] 6 एस सी आर।

6.7 अब जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में नीलामी मंच के आवंटन का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाजार समिति और प्रत्यर्थी संख्या 5 के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 5 के पास 1970 से लाइसेंस है और वह व्यवसाय कर रहा है, जबकि इसमें अपीलकर्ता को 16.07.2007 पर लाइसेंस मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रासंगिक समय पर जब नवनिर्मित शेड का आवंटन किया गया था, प्रतिवादी संख्या 5 के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था और/या नवीनीकरण न होने के कारण वैध नहीं था और लाइसेंस देने का मामला समिति के कार्यालय में विचार के लिए लंबित था, जिसे फरवरी, 2010 के महीने में दिया गया था। इसके बाद, बाजार समिति के लाइसेंसधारी होने और शेड के ढहने से पहले शेड के कब्जे में होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में शेड आवंटित किया गया है। प्रतिनिधित्व तय करते समय बाजार समिति द्वारा इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है।

/

/

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और इसके विपरीत किसी विशिष्ट नियम/विनियम के अभाव में और जब कृषि सचिव के सिद्धांतों/दिशानिर्देशों के अनुसार शेड का आवंटन किया जाता है, तो अपीलकर्ता के पक्ष में कोई विशिष्ट नियम के अभाव में, उसकी दुकान के ठीक सामने और/या उसके बगल में आवंटन का दावा करने का अधिकार और जब नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में आवंटन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने अपीलकर्ता के खिलाफ उचित निर्णय लिया है और रिट याचिकाओं और अपीलों को सही ढंग से खारिज कर दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

/

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों में योग्यता की कमी है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/